

प्रेषक,

डॉ०एम०सी०जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3,

देहरादून, दिनांक: 09 मार्च, 2015

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवश्यकता से न्यून धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से करते हुए धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० अर्थ-1/30957/5क(15)/01/2014-15 दिनांक: 06 जनवरी, 2015 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिष्ठान संबंधी कतिपय मानक मदों के अन्तर्गत आय-व्ययक में आवश्यकता से कम धनराशि प्राविधानित होने के कारण मानक मद अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता में आवश्यकतानुसार भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु संलग्नक बी०एम०-09 (भाग एक) में इंगित विवरणानुसार अनुदान संख्या: 11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रु० 1650 हजार तथा महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत मानक मद गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद में आवश्यकतानुसार भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु संलग्नक बी०एम०-09 (भाग एक) में इंगित विवरणानुसार अनुदान सं० 11-आयोजनागत पक्ष में रु० 75 हजार इस प्रकार कुल रु० 1725 हजार (रुपये सत्रह लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (क) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है एवं व्यय करते समय विभागीय तथा वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ख) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (ग) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 318/XXVII (1)/2014, दिनांक: 18.03.2014 एवं शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012, दिनांक: 28.03.2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।
- (ङ) मितव्ययिता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- (च) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है कि उस मद में कदापि अतिरिक्त धनराशि की मांग न की जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान सं० 11 आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संलग्नकों (बी०एम०-09) में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 88 (NP)/XXVII (3)2014-15 दिनांक: 03 मार्च, 2015 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ०एम०सी० जोशी)
सचिव।

(2)

पृष्ठांकन संख्या: 45/XXIV-3/15/02(141)2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव-सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 3- जिलाधिकारी देहरादून।
- 5- कोषाधिकारी देहरादून।
- 6- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 7- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- ✓ 9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

M. K. M.

(महिमा)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2014-2015)
बी.एम. - 09

(दान संख्या - 011)

पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 45/XXIV-3/15/02(141)201

अलोटमेंट आईडी - R1503110270
दिनांक - 07-Mar-2015

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाविवरण (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाविवरण वित्तमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	(In Rupees) अभियन्ता
	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान 00 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान (Non Plan Voted)				2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान 00 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान (Non Plan Voted)			
1	01 - वेतन 23000000	19781403	2618597	600000	06 - अन्य धन 550000	3080000	22400000	
2	03 - नहंगाई भत्ता 25300000	17862580	6387420	1050000	08 - कार्यालय व्यय 90000	590000	24250000	
	योग			1650000	16 - स्वास्थ्याधिक तथा विशेष सेवाओं 1000000	2000000		
					22 - अतिरिक्त व्यय नियमक नता आदि 10000	00000		
					योग 1650000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेंटर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध करायी

41477
(महिमा)
उपसचिव
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2014-2015)

बी.एम. - 09

दान संख्या - 011

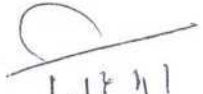
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 45/XXIV-3/15/02(141)201

अलोटमेंट आईडी - R1503110268
दिनांक - 07-Mar-2015

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखासिर्जक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस तथा खोजित धनराशि (4)	लेखाधीनक विषये धनराशि स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशि (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशि	(in Rupees) अभिवृत्ति
	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कार्यालय 00 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय (Plan Voted)				2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा काय 00 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय (Plan Voted)			
1	19 - विज्ञापन, बिजली और विद्युत 200000	0	125000	75000	15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल 75000	125000	125000	
	योग			75000	योग 75000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेक्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध करायी


 (महिला)
 उपसचिव
 विद्यालयी शिक्षा
 उत्तराखण्ड शासन